नईदुनिया

संपादकीय

लंबी उम्र नहीं, स्वस्थ जीवन की जरूरत

भारत में महिलाओं की औसत आयु लगातार बढ़ रही है, जो स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन स्तर में सुधार का संकेत है। लेकिन इसके साथ एक चिंताजनक सच्चाई भी सामने आ रही है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक वर्ष जीवित रहती हैं, परंतु उनके जीवन का बड़ा हिस्सा बीमारियों, कमजोरी और उपचार के बीच गुजरता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार भारत में महिलाओं की औसत आयु लगभग 69 वर्ष है, जबकि पुरुषों की 65.5 वर्ष है। इसके बावजूद महिलाओं का स्वस्थ जीवनकाल अपेक्षाकृत कम है। यानी लंबी उम्र मिल रही है, लेकिन स्वस्थ जीवन नहीं।

इस स्थिति के पीछे कई कारण हैं। देश में 15 से 49 वर्ष की लगभग 57 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। बचपन से पर्याप्त पोषण न मिलना, किशोरावस्था में आयरन और कैल्शियम की कमी तथा गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य की अनदेखी जीवनभर उनका साथ नहीं छोड़ती। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और जागरूकता का अभाव समस्या को और गंभीर बना देता है, जबकि शहरों में अनियमित जीवनशैली, तनाव, व्यायाम की कमी और असंतुलित खानपान नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।

भारतीय महिलाओं पर घर और कार्यस्थल की दोहरी जिम्मेदारी भी स्वास्थ्य पर भारी पड़ती है। परिवार की देखभाल में वे अपने स्वास्थ्य को सबसे अंत में रखती हैं। थकान, कमजोरी या दर्द को सामान्य मानकर टाल देती हैं और जब तक जांच कराती हैं, तब तक बीमारी गंभीर रूप ले चुकी होती है। यही कारण है कि अब मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गैर-संचारी बीमारियां पहले की तुलना में कम उम्र में ही दिखाई देने लगी हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी एक बड़ी चुनौती है। अवसाद और चिंता की समस्या महिलाओं में अधिक पाई जाती है, लेकिन इलाज कराने वाली महिलाओं की संख्या आज भी बहुत कम है।

इस स्थिति को बदलने के लिए केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं होंगी। पोषण अभियान, आयुष्मान भारत और मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभाव तभी बढ़ेगा, जब उनका क्रियान्वयन गांव-गांव तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। स्कूल स्तर से ही लड़कियों के पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच और आयरन-फोलिक एसिड की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। परिवारों को भी बेटा-बेटी के बीच भोजन, शिक्षा और उपचार में भेदभाव समाप्त करना होगा।

महिलाओं को भी यह समझना होगा कि परिवार की देखभाल के साथ स्वयं का स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच अनेक बीमारियों से बचा सकती है। कार्यस्थलों पर भी महिला कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच और मानसिक परामर्श जैसी सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए।

भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। यह लक्ष्य तभी सार्थक होगा, जब देश की आधी आबादी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगी। महिलाओं की बढ़ती आयु निश्चित रूप से सुखद संकेत है, लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि यह अतिरिक्त जीवन बीमारी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सम्मान और सक्रियता के साथ बीते। स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ भारत की सबसे मजबूत आधारशिला है।

आजकल

देर से शादी का बदलता सामाजिक गणित

भारत में महिलाओं की शादी की औसत उम्र 19.3 वर्ष से बढ़कर 23.1 वर्ष हो गई है। शहरों में यह 24.4 वर्ष और गांवों में 22.6 वर्ष तक पहुंच चुकी है। यह बदलाव केवल एक सांख्यिकीय तथ्य नहीं, बल्कि बदलते भारतीय समाज की नई तस्वीर है। शिक्षा, करियर, आर्थिक आत्मनिर्भरता और बढ़ती जागरूकता ने विवाह की पारंपरिक सोच को बदलना शुरू कर दिया है।

आज अधिकतर परिवार चाहते हैं कि बेटियां पहले उच्च शिक्षा प्राप्त करें, रोजगार हासिल करें और आर्थिक रूप से सक्षम बनें। बढ़ती महंगाई और घर बसाने की लागत ने भी विवाह की उम्र बढ़ाने में भूमिका निभाई है। साथ ही, किशोर विवाह रोकने और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण को लेकर चलाए गए सरकारी अभियानों का भी सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है।

इस बदलाव के कई लाभ हैं। देर से विवाह होने पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य बेहतर रहता है, किशोरावस्था में गर्भधारण की आशंका घटती है और महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ती है। छोटे परिवार बनने से शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति निवेश भी बढ़ सकता है।

इसके कुछ दीर्घकालिक प्रभाव भी सामने आ सकते हैं। देर से विवाह और मातृत्व के कारण प्रजनन दर में लगातार गिरावट आ रही है। कई राज्यों में यह पहले ही प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंच चुकी है। भविष्य में कामकाजी युवाओं की संख्या घटने और बुजुर्ग आबादी बढ़ने से पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा पर दबाव बढ़ सकता है। विवाह की बदलती आयु सामाजिक संरचना और विवाह बाजार को भी प्रभावित करेगी।

विवाह की बढ़ती उम्र महिला सशक्तिकरण का सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसके साथ बदलती जनसांख्यिकीय चुनौतियों को भी समझना होगा। सरकार को शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षित रोजगार और वृद्धजन देखभाल की नीतियों पर समानांतर रूप से काम करना होगा। तभी यह सामाजिक बदलाव देश के विकास का आधार बन सकेगा।

यूके व्यापार समझौते से प्रत्येक भारतीय के लिए बड़े अवसर खुलेंगे

पीयूष गोयल
(लेखक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं)

भारतीय युवाओं के लाभ के लिए, यूके ने अब तक की अपनी सबसे व्यापक सेवा-संबंधी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिसमें सभी प्रमुख सेवा क्षेत्र और भारत के लिए निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण 137 उप-क्षेत्र शामिल हैं। बेहतर बाजार पहुँच और नियामक स्पष्टता से भारतीय सेवा प्रदाताओं को आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, पेशेवर सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श सेवाओं में समर्थन मिलेगा। रोज़गार के अवसर-युवाओं को रोज़गार के ज़्यादा मौके मिलेंगे, क्योंकि बेहतर पहुँच के साथ रत्न और आभूषण, वस्त्र, चमड़ा और जूते, जैविक रसायन, प्लास्टिक, वाहन कल-पुर्जे, हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम-गहन क्षेत्र अपने कामकाज का विस्तार करेंगे।

आज से, यूके को होने वाले भारत के लगभग सभी निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। इससे हमारे छोटे व्यवसायों, किसानों, मछुआरों, नवोन्मेषकों, महिलाओं और श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए बड़े अवसर खुलेंगे, क्योंकि परिवर्तनकारी 'व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता' (सीईटीए) आज से लागू हो रहा है।

यह भारत का सबसे व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है और यह बड़ी संख्या में नौकरियों और व्यापार-अवसरों का सृजन करके समृद्धि लाएगा। इससे भारतीय निर्माताओं को धीरे-धीरे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा और हर नागरिक को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले सामान प्राप्त करने का लाभ मिलेगा। इससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 मिशन को भी तेज गति मिलेगी।

व्यवसायियों में उत्साह है। उनके पास यूके को माल भेजने के लिए विस्तृत योजनाएं हैं। रत्न और आभूषण निर्यातकों को उम्मीद है कि यूके को होने वाला निर्यात अगले तीन साल या उससे भी कम समय में 230 प्रतिशत बढ़कर 2.5 अरब डॉलर हो जाएगा, जबकि इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यातकों को उम्मीद है कि अगले 4-5 सालों में यूके को होने वाली बिक्री लगभग दोगुनी होकर 7.5 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगी।

पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए इस समझौते से, जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है, लगभग 99 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएगा। इसमें लगभग 100 प्रतिशत व्यापार मूल्य शामिल है, जिससे भारतीय निर्यात, जो वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद पहले से ही तेज़ी से बढ़ रहा है, के लिए अपार अवसर पैदा होंगे।

युवा सोच, वैश्विक अवसर- यह जन-केंद्रित एफटीए 15 जुलाई से लागू हो रहा है, जो विश्व युवा कौशल दिवस भी है। 2015 में इसी दिन पीएम मोदी ने कौशल भारत मिशन की शुरुआत की थी, जो हमारे युवाओं को न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने, योगदान देने और नेतृत्व करने में सक्षम बना रहा है।

भारतीय युवाओं के लाभ के लिए, यूके ने अब तक की अपनी सबसे व्यापक सेवा-संबंधी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिसमें सभी प्रमुख सेवा क्षेत्र और भारत के लिए निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण 137 उप-क्षेत्र शामिल हैं। बेहतर बाजार पहुँच और नियामक स्पष्टता से भारतीय सेवा प्रदाताओं को आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, पेशेवर सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श सेवाओं में समर्थन मिलेगा।

रोज़गार के अवसर-युवाओं को रोज़गार के ज़्यादा मौके मिलेंगे, क्योंकि बेहतर पहुँच के साथ रत्न और आभूषण, वस्त्र, चमड़ा और जूते, जैविक रसायन, प्लास्टिक, वाहन कल-पुर्जे, हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम-गहन क्षेत्र अपने कामकाज का विस्तार करेंगे।

कुल मिलाकर, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं तक पहुंच को बढ़ावा देकर और प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार करके, सीईटीए भारतीय युवाओं को जरूरी कौशल और अवसर प्रदान करेगा, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सार्थक भूमिका निभा सकें और विकास में योगदान दे सकें।

सीईटीए का एक महत्वपूर्ण पहलू है, दोहरी योगदान व्यवस्था। यह ऐतिहासिक व्यवस्था, जो सीईटीए के साथ लागू हो रही है, भारतीय श्रमिकों और नियोक्ताओं को अस्थायी कार्य-भार के दौरान यूके में दोहरी सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट देती है।

कर्मचारियों के लिए अस्थायी विदेशी कार्य-भार पर निरंतर सामाजिक सुरक्षा कवरेज से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से अधिक कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

स्थानीय स्तर पर उगाएं, वैश्विक स्तर पर बेचें-भारतीय किसानों को 37.5 बिलियन डॉलर के ब्रिटेन के बाजार तक आसान पहुंच से फायदा होगा। इससे भारतीय डेयरी उत्पादों, चाय, कॉफी, मसालों, फलों, सब्जियों, फलों के रस, मांस और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। यूके के लगभग 95 प्रतिशत कृषि आयात भारत के लिए शुल्क- मुक्त होंगे। इस विशाल बाजार में निर्यात तीन वर्षों में 50 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि मूल्य श्रृंखला में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समझौते में डेयरी, सब्जियां, सेब, खाद्य तेल, जई (ओट्स), मोटे अनाज, कुकिंग ऑयल और अन्य जैसे संवेदनशील कृषि उत्पादों को पूरी सुरक्षा दी गई है और इन्हें संवेदनशील सूची में रखा गया है। इन वस्तुओं पर ब्रिटेन को कोई सीमा-शुल्क छूट नहीं दी गई है। ये अपवाद मोदी सरकार की खाद्य सुरक्षा, घरेलू मूल्य स्थिरता और कमजोर कृषि समुदायों को प्राथमिकता देने की रणनीति को दर्शाते हैं।

एसएमई - स्थानीय प्रयास, वैश्विक ताकत - पीएम मोदी ने हमेशा से भारत के लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को उच्च प्राथमिकता दी है। सीईटीए में महत्वपूर्ण एसएमई क्षेत्र की मदद के लिए एक विशेष अध्याय है, 2024-25 में भारत के कुल निर्यात में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 45.8 प्रतिशत थी। सीईटीए कई प्रमुख प्रावधानों के साथ एसएमई की मदद करेगा, जैसे तेज सीमा-शुल्क प्रक्रिया, डिजिटल प्रणालियों और दस्तावेज रहित व्यापार को मान्यता देने और सुविधाजनक बनाने के समझौते।

बाजार तक प्राथमिक पहुंच के अलावा, एसएमई को व्यापार, शिक्षा और वित्त, डिजिटल कौशल, व्यवसायिक अवसंरचना और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी सर्वोत्तम प्रथाओं पर बढ़ते सहयोग का भी लाभ मिलेगा।

मछुआरों के लिए बड़ी खुशी-सीईटीए से भारत के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है, जो लगभग 28 मिलियन लोगों की आजीविका का ज़रिया है।

बाज़ार तक बेहतर पहुँच और ज़्यादा निर्यात से आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और महाराष्ट्र के मछुआरों को लाभ होगा। इससे न सिर्फ़ भारत के मत्स्य निर्यात को मज़बूती मिलेगी, बल्कि मछुआरों की भलाई और आजीविका में भी मदद मिलेगी और तटीय इलाकों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

महिलाओं के लिए बड़ी जीत - यह ऐतिहासिक समझौता, जो पारंपरिक एफटीए से कहीं अधिक है, सतत और समावेशी आर्थिक विकास में महिलाओं के योगदान को मान्यता देता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए अवसर और लाभ को बढ़ावा देना है।

दोनों देशों ने महिलाओं की बाज़ार और उभरते क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाने, वित्तीय समावेश और साक्षरता को बढ़ावा देने, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करने, और उनकी क्षमता और कौशल विकसित करने जैसी विभिन्न गतिविधियाँ का वादा किया है।

सीईटीए सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है। यह भारत की क्षमताओं और आकांक्षाओं में विश्वास का एक वक्तव्य है। यह एक नए भारत को प्रतिबिंबित करता है, जो सिर्फ वैश्विक व्यापार में भाग ही नहीं ले रहा है, बल्कि इसे आकार देने में भी मदद कर रहा है। हमारे किसानों, मछुआरों, कामगारों, महिला उद्यमियों, एमएसएमई, पेशेवरों और युवाओं को सशक्त बनाकर, यह समझौता देश के प्रत्येक हिस्से में रह रहे हर भारतवासी को अवसर उपलब्ध कराएगा।

लड़ता पंजाब में कांग्रेस खुद से लड़ रही है...

अंतर्कलह ने डुबोई 2022 की नैया, अब 2027 की तैयारी भी खतरे में

पंजाब की सियासत में एक पुरानी कहावत है कि यहां सरकारें सड़कों पर नहीं, बल्कि गुरुद्वारों और पंचायतों में बनती हैं। लेकिन 2022 के बाद कांग्रेस ने इस कहावत को मानो नए सिरे से लिख दिया है कि यहां सरकारें नहीं, बल्कि पार्टियां अपने ही घर में हारती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी को उम्मीद थी कि आत्ममंथन होगा, संगठन मजबूत होगा और नेतृत्व एकजुट होकर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरेगा। हुआ इसके उलट। चेहरे बदले, कमान बदली, समितियां बनीं, लेकिन आग बुझने के बजाय और भड़क गई। प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल की मौजूदगी में हुई बंद कमरे की बैठक में जो कुछ हुआ, उसने कांग्रेस के 'लड़ता पंजाब' के नारे की हवा निकाल दी।

बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सीधे प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर निशाना साधते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर दी। जवाब में पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने चन्नी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्हें 'कंप्रोमाइज्ड' नेता तक कह दिया। आरोप इतने निजी और तीखे थे कि बैठक सुलह का मंच बनने के बजाय अखाड़ा बन गई। अब सवाल यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह है कि 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस इस स्थिति तक पहुंची कैसे।

यदि इसकी जड़ों में जाएं तो यह कलह नई नहीं है। इसकी शुरुआत 2021 में ही दिखाई देने लगी थी, जब कांग्रेस आलाकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। इसके पीछे दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति थी। पंजाब में लगभग 32 प्रतिशत दलित आबादी है और कांग्रेस को उम्मीद थी कि चन्नी के नेतृत्व से उसे राजनीतिक लाभ मिलेगा। लेकिन चुनाव परिणामों ने साबित कर दिया कि केवल जातीय समीकरण जीत की गारंटी नहीं होते। संगठन की कमजोरी और आम आदमी पार्टी की लहर के सामने यह रणनीति विफल रही।

हार के बाद पार्टी ने एक और प्रयोग किया। अमरिंदर के जाने के बाद राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वे युवा और आक्रामक नेता हैं तथा शहरी और हिंदू मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पार्टी के पुराने नेताओं को लगा कि उन्हें हाशिए पर धकेला जा रहा है। यहीं से असंतोष ने आकार लेना शुरू किया। पिछले कई महीनों से नाराज गुटों की बंद कमरों में बैठकें चल रही थीं और भूपेश बघेल की बैठक उन्हें खुलकर सामने आने का अवसर दे गई।

चन्नी का तर्क है कि वड़िंग के नेतृत्व में दलित वोट बैंक खिसक रहा है और उन्हें फिर से केंद्रीय भूमिका मिलनी चाहिए। दूसरी ओर रंधावा स्वयं को जाट सिख नेतृत्व के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। उनका आरोप है कि मौजूदा प्रदेश नेतृत्व सरकार के सामने नरम रवैया अपनाए हुए है। वहीं वड़िंग ने भी पलटवार करते हुए रंधावा की केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात का उल्लेख कर उन्हें भाजपा का 'स्लीपर सेल' तक बता दिया। आरोपों का स्तर इतना नीचे पहुंच चुका है कि संगठनात्मक अनुशासन की बात भी बेमानी लगने लगी है।

इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लड़ाई मुद्दों पर नहीं, बल्कि नेतृत्व और वर्चस्व पर केंद्रित है। नशा, बेरोजगारी, किसान संकट, उद्योग और सीमा सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पीछे छूट गए हैं। जब नेता सार्वजनिक मंचों से एक-दूसरे पर हमला करते हैं तो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटता है। पिछले पांच वर्षों में कांग्रेस ने पंजाब में कई बार नेतृत्व बदला, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। अब आलाकमान के सामने तीन विकल्प हैं। पहला, अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई कर स्पष्ट संदेश देना। दूसरा, सभी प्रमुख नेताओं को साथ लेकर सामूहिक नेतृत्व का फार्मूला अपनाना। तीसरा, किसी नए और तटस्थ चेहरे को आगे लाना। हालांकि पंजाब जैसे राज्य में ऐसा सर्वमान्य चेहरा तलाशना आसान नहीं होगा।

इस अंतर्कलह का सबसे बड़ा नुकसान पंजाब की जनता को हो रहा है। राज्य किसान संकट, नशे, बेरोजगारी, पलायन, उद्योगों की सुस्ती और सीमा सुरक्षा जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में विपक्ष की भूमिका मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस अपने ही अंतर्विरोधों में उलझी हुई है। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पार्टी एकजुट थी और सत्ता में आई। 2022 में वही एकजुटता टूटी तो पार्टी 18 सीटों तक सिमट गई। यदि यही स्थिति बनी रही तो 2027 में उसके सामने अस्तित्व का संकट भी खड़ा हो सकता है। कांग्रेस को समझना होगा कि पंजाब में केवल जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पर्याप्त नहीं हैं। सबसे अधिक जरूरत विश्वसनीय नेतृत्व और मजबूत संगठन की है। कार्यकर्ता तभी पूरी ताकत से मैदान में उतरता है, जब उसे विश्वास हो कि उसके नेता पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, न कि केवल अपनी राजनीतिक स्थिति बचाने के लिए। अब समय आधे-अधूरे फैसलों का नहीं, बल्कि स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति का है। यदि कांग्रेस अपने भीतर की लड़ाई नहीं रोक सकी तो 'लड़ता पंजाब' का नारा केवल पोस्टरों तक सीमित रह जाएगा और जनता एक बार फिर उसे विपक्ष की भूमिका के योग्य भी नहीं मानेगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

फिट पुलिस, फिट तंत्र...

यदि वर्दी तंदुरुस्त होगी तो कानून-व्यवस्था भी मजबूत होगी। पुलिस को समाज का दर्पण कहा जाता है। जिस राज्य की पुलिस जितनी चुस्त और तंदुरुस्त होगी, उस राज्य का कानून-व्यवस्था तंत्र भी उतना ही मजबूत होगा। पर पिछले कई वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि पुलिस की ड्यूटी की प्रकृति और बढ़ते कार्यभार के कारण उनके अपने स्वास्थ्य पर सबसे अधिक असर पड़ रहा है। लगातार लंबी ड्यूटी, घंटों खड़े होकर यातायात संभालना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना, त्योहारों और वीआईपी ड्यूटी में रातभर जागना-इन सबके कारण पुलिसकर्मियों की दिनचर्या पूरी तरह बिगड़ गई है। न खाने का समय तय है, न सोने का और न ही परिवार के साथ बैठने का अवसर मिल पाता है।

ऐसी परिस्थितियों में शरीर धीरे-धीरे जवाब देने लगता है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा और मानसिक तनाव पुलिस विभाग में आम समस्याएं बन चुकी हैं। थाने में बैठा अधिकारी फाइलों के बोझ से दबा है, तो मैदान में तैनात जवान धूप, बारिश और भीड़ के दबाव से जूझ रहा है। दोनों ही समान रूप से शारीरिक और मानसिक थकान का सामना कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर मानव शरीर कब तक इस तरह लगातार काम कर सकता है? मशीन भी बिना रुके चलती रहे तो गर्म हो जाती है, फिर इंसान तो आखिर इंसान ही है।

ऐसे में यदि पुलिस विभाग ने फिटनेस पर ध्यान देने की पहल शुरू की है तो यह बेहद सराहनीय कदम है। यह केवल पुलिसकर्मियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। फिटनेस का अर्थ केवल परेड और दौड़ नहीं है। इसका मतलब नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित भोजन, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और काम के बीच पर्याप्त विश्राम भी है।

यातायात पुलिस घंटों धूप, धूल और शोर के बीच ड्यूटी करती है। कानून-व्यवस्था में तैनात जवान भीड़ को नियंत्रित करता है और रात में गश्त करता है। यदि उसे समय पर भोजन और पर्याप्त आराम नहीं मिलेगा तो उसकी सतर्कता कैसे बनी रहेगी? थका हुआ दिमाग गलत निर्णय ले सकता है और एक गलत निर्णय किसी की जान पर भी भारी पड़ सकता है। इसलिए फिटनेस को अब सुविधा नहीं, बल्कि आवश्यकता के रूप में देखा जाना चाहिए।

फिट पुलिस से पूरे तंत्र में कसावट आएगी। जब जवान शारीरिक रूप से मजबूत होगा तो वह अपराधियों से बेहतर तरीके से निपट सकेगा। जब अधिकारी मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो वह जनता की समस्याओं को अधिक संवेदनशीलता से सुनेगा। जब थाने का वातावरण सकारात्मक होगा तो वहां आने वाला फरियादी भी विश्वास के साथ अपनी बात रख सकेगा। आज अक्सर शिकायत सुनने को मिलती है कि पुलिस चिड़चिड़ी हो गई है या लोगों की बात ठीक से नहीं सुनती। लेकिन इसके पीछे लगातार काम का दबाव और अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा भी एक बड़ा कारण है।

अब समय आ गया है कि हर जिले और हर थाने में फिटनेस को प्राथमिकता दी जाए। सप्ताह में एक दिन सामूहिक योग और व्यायाम कराया जाए। थानों में बेसिक जिम की सुविधा उपलब्ध हो। लंबी ड्यूटी के बाद विश्राम कक्ष बनाए जाएं। भोजन के समय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और वर्ष में कम से कम दो बार सभी पुलिसकर्मियों की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य की जाए।

इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को भी उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। जब बड़े अधिकारी स्वयं फिट रहेंगे, सुबह परेड में शामिल होंगे और जवानों के साथ मैदान में दौड़ लगाएंगे, तब नीचे तक यह संदेश जाएगा कि फिटनेस कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि ड्यूटी का अभिन्न हिस्सा है।

समाज को भी यह समझना होगा कि पुलिसकर्मी भी इंसान हैं। उनसे चौबीसों घंटे मशीन की तरह काम लेने की अपेक्षा उचित नहीं है। त्योहारों पर जब हम अपने परिवार के साथ उत्सव मना रहे होते हैं, तब वही पुलिसकर्मी सड़क पर हमारी सुरक्षा में तैनात रहता है। इसलिए व्यवस्था से यह अपेक्षा भी होनी चाहिए कि पुलिस की ड्यूटी में मानवीय पक्ष का पूरा ध्यान रखा जाए।

यह पहल केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रोज अपराध, दुर्घटनाएं, लाशें, पारिवारिक विवाद और तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने का असर पुलिसकर्मियों के मन पर भी पड़ता है। इसलिए नियमित काउंसलिंग और तनाव प्रबंधन के कार्यक्रम भी आवश्यक हैं, ताकि वर्दी के भीतर का इंसान भी स्वस्थ रह सके।

यदि यह अभियान गंभीरता से लागू हुआ तो इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। अपराध नियंत्रण बेहतर होगा, पुलिस का रिस्पांस टाइम घटेगा और पुलिस तथा जनता के बीच विश्वास मजबूत होगा। एक फिट पुलिसकर्मी अधिक ऊर्जा, संवेदनशीलता और दक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेगा। देश की सुरक्षा सेना करती है और समाज की सुरक्षा पुलिस। यदि सेना को फिट रखना आवश्यक है तो पुलिस को फिट रखना भी उतना ही जरूरी है। यह पहल देर से सही, लेकिन सही दिशा में उठाया गया कदम है। अब इसे केवल फाइलों तक सीमित न रखकर जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, ताकि हर थाने और हर चौकी से यह संदेश जाए-हम फिट हैं, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। वर्दी तंदुरुस्त होगी तभी तंत्र में कसावट आएगी और जब तंत्र मजबूत होगा, तभी आम आदमी चैन की नींद सो सकेगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)